**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1446**

**24दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का कार्य निष्पादन**

**1446.श्री आर. वैद्यलिंगम:**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि डीआरडीओ और इसकी 52 प्रयोगशालाओं के चार रक्षा शिपयार्डों, सार्वजनिक क्षेत्र के पांच रक्षा उपक्रमों और 41 आयुध फैक्टरियों के बहुत खराब कार्यनिष्पादन के कारण हथियारों के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि डीआरडीओ को अधिक शक्तियां दिये जाने का आशय यह था कि अधिक केन्द्रीयकरण के दुष्प्रभावों को समाप्त किया जाए और शीघ्र निर्णय लेने को सुकर बनाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतामरण)**

(क)एवं (ख): डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने बड़ी संख्या में हथियार प्रणालियों,प्लेटफार्मोंऔर रक्षा उपस्करों का विकास किया है जिन्हें रक्षा सेनाओं द्वारा पहले शामिल कर लिया गया है/जो शामिल किए जाने के लिए तैयार हैं। ये प्रणालियां उच्च स्वदेशीकरण सामग्री और आत्म निर्भरता के साथ विश्व में सर्वोत्तम प्रणालियों से तुलनीय हैं। डीआरडीओ स्वदेशी रूप से विकसित उप-प्रणालियों/अवयवों के साथ अपने उत्पादों में आयात मात्रा को प्रतिस्थापित करने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रहा है ताकिप्रतिबंध/शास्ति द्वारा इसमें अवरोधउत्पन्न न हो। डीआरडीओ द्वारा विकसित और सेनाओं में शामिल अथवा शामिल किए जाने की प्रक्रिया में प्रणालियों/उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का मूल्य 2.72 लाख करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों में सामरिक प्रणालियां शामिल नहीं हैं।

(ग) एवं (घ): डीआरडीओ को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को हाल ही में संशोधित किया गया है। परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रत्यायोजित संशोधित वित्तीय शक्तियां सचिव, रक्षा, आरएंडडी 150 करोड़ रुपये तक, महानिदेशक, क्लस्टर 75 करोड़ रुपये और निदेशक, प्रयोगशाला 5 करोड़ रुपये तक है। दैनिक कार्यकरण के विकेन्द्रीकरण और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और स्वदेशी रक्षा उद्योग में रक्षा अनुसंधान को प्रायोजित और प्रोत्साहित करने में लचीलापन लाने के लिए अन्य प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं।

\*\*\*\*